आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)

गुरुवार 11.12.2025 समय 1830

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के डीएफओ को हटाने के निर्देश दिए। जंगली जानवरों से प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को एस्कार्ट की सुविधा मिलेगी।
- मुख्यमंत्री धामी ने पीआरडी जवानों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की।
- कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अल्मोड़ा में कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास और सैनिक कल्याण विभागों के कार्यों की समीक्षा की।
- रुद्रप्रयाग जिले की दरमोला ग्राम सभा में "वन उपज से आजीविका संवर्धन" पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न।

वन विभाग समीक्षा

प्रदेश में जंगली जानवरों से ज्यादा खतरे वाले क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और घर तक लाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन एस्कॉर्ट की व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने पौड़ी में मानव–वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत पौड़ी के प्रभागीय वनाधिकारी को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाने के भी निर्देश दिए। मानव वन्यजीव संघर्ष को खत्म करने के लिए वन विभाग के साथ ही शासन–प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष घटना की सूचना मिलने के 30 मिनट के अन्दर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करेगी। इसके लिए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मानव–वन्यजीव संघर्ष में किसी परिवार से कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग प्रभावित परिवार की आजीविका को सहायता देने के लिए दो सप्ताह के अंदर नीति बनाकर प्रस्तुत करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी वन्यजीवों से लोगों के जीवन को बचाना है। उन्होंने इसके लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बस्तियों के आस–पास झाड़ियों को अभियान चलाकर साफ करने और बच्चों व महिलाओं को विशेष तौर पर आस–पास वन्य जीवों की मौजूदगी को लेकर जागरुक करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

प्रांतीय रक्षक दल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रांतीय रक्षक दल– पीआरडी जवानों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की। श्री धामी ने आज देहरादून में पीआरडी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीआरडी जवानों को भी अब ड्यूटी के दौरान अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में उपचार के दौरान ड्यूटी पर ही माना जाएगा और उन्हें अधिकतम छह माह का मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रायपुर के ग्राम अस्थल में खेल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पी.आर.डी जवान, धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छाशक्ति के साथ प्रदेश में सुरक्षा और जनसेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिवंगत पीआरडी स्वयं सेवकों के आश्रितों को सहायता राशि और पीआरडी जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति के चेक प्रदान किए।

राज्यसभा सांसद प्रश्न

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में उत्तराखंड से सांसद महेन्द्र भट्ट द्वारा हरिद्वार में होने वाले आगामी महाकुंभ की तैयारी से संबंधित पूछे गए लिखित प्रश्न का उत्तर दिया। श्री शेखावत ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय राज्यों–संघ राज्य क्षेत्रों में मेलों और महोत्सवों के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों–संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को घरेलू प्रचार और आतिथ्य योजना के दिशा–निर्देशों के तहत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि मंत्रालय को अभी तक उत्तराखंड के हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के लिए राज्य सरकार से इस योजना के तहत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कृषि मंत्री

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज अल्मोड़ा में कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास और सैनिक कल्याण विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में लखपति दीदी योजना, पलायन रोकथाम योजना, ऐपल मिशन, मौन पालन व मधुग्राम के रूप में ग्रामों का विकास तथा पॉलीहाउस स्थापना पर विशेष कार्य करने पर जोर दिया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएं सीधे किसानों और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका से जुड़ी हैं, इसलिए प्रत्येक लाभार्थी तक योजनाओं का शत–प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय बनाकर जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए ठोस प्रयास सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण कार्यशाला

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के दक्षिणी जखोली रेंज के दरमोला ग्राम सभा में ग्रामीणों के लिए आयोजित "वन उपज से आजीविका संवर्धन" पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आज सम्पन्न हो गई। प्रशिक्षण में ग्रामीणों को पिरूल, छेंती, बांस और घास जैसी स्थानीय वन उपज से उपयोगी और आकर्षक उत्पाद तैयार करने की कला सिखाई गई। विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को राखी, सजावटी वस्तुएँ, टोकरी, पैन होल्डर, फ्लावर पॉट और विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण व्यावहारिक रूप से सिखाया। उप प्रभागीय वनाधिकारी डॉ. दिवाकर पन्त ने बताया कि बदलती जीवनशैली और बाजार की मांग को देखते हुए स्थानीय वन उपज पर आधारित हस्तशिल्प उत्पादों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए यह प्रशिक्षण एक सशक्त अवसर है, जिससे वे अपने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक स्वरूप देकर वित्तीय रूप से सशक्त बन सकते हैं। प्रशिक्षण में शामिल ग्रामीण महिलाओं ने इस पहल को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए अवसर प्रदान करना था।

एथलेटिक्स प्रतियोगिता

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुल सचिव देवेंद्र सिंह बिष्ट ने आज बागेश्वर में अंतर महाविद्यालयी पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 22 महाविद्यालयों के 145 खिलाड़ियों ने भाग लेकर शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कुल सचिव ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अवसर देती हैं। उन्होंने बताया कि यहां से चयनित खिलाड़ी नॉर्थ जोन और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर खेल का प्रदर्शन कर प्रदेश और विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाएंगे।

छात्रवृत्ति पोर्टल

समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल आगामी 24 दिसंबर तक खोला गया है। इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित उच्च शैक्षणिक संस्थान के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है। रुद्रप्रयाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी टीआर मलेठा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों की सुविधा के दृष्टिगत 24 दिसंबर तक की तिथि विस्तारित की गई है, ताकि छात्रवृत्ति योजना के तहत पोर्टल पर अधिक से अधिक छात्र–छात्राएं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकें।